

खंड: 7, अंक: 6

जून 2024

RNI- DELHIN/2021/84711

ISSN- 2584-2803 (Print)

# संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

लोकसभा चुनाव 2024:  
प्रदर्शन, परीक्षण एवं प्रभाव



Aiming High, Touching Sky

सी जी एस  
वैश्विक अध्ययन केंद्र  
(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)  
दिल्ली विश्वविद्यालय

LOK SABHA ELECTIONS 2024



## संपादक

### **प्रोफेसर सुनील कुमार**

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: [director@cgs.du.ac.in](mailto:director@cgs.du.ac.in)

प्रोफाइल लिंक: <https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html>

## संपादक मंडल

### **डॉ रमेश कुमार भारद्वाज**

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337  
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: [rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in](mailto:rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in)

प्रोफाइल लिंक: <https://www.mphighereducation.nic.in>

### **डॉ महेश कौशिक**

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017  
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: [mkaushik@cgs.du.ac.in](mailto:mkaushik@cgs.du.ac.in)

प्रोफाइल लिंक: <https://www.aurobindo.du.ac.in>

### **डॉ संध्या वर्मा**

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032  
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: [sverma@shyاملale.du.ac.in](mailto:sverma@shyاملale.du.ac.in)

प्रोफाइल लिंक: <https://shyاملale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf>

### **डॉ अभिषेक नाथ**

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार

ई-मेल आई डी: [tuesdaytrack@gmail.com](mailto:tuesdaytrack@gmail.com)

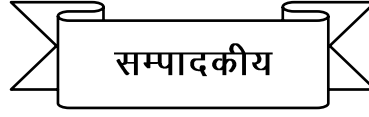
प्रोफाइल लिंक: <https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3>

लोकसभा चुनाव 2024: प्रदर्शन, परीक्षण एवं प्रभाव

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. भारतीय चुनावी व्यवस्था: लोकसभा चुनाव 2024 का एक अध्ययन  
– नविता कुमारी 1–4
2. लोकसभा चुनाव 2024: विश्लेषणात्मक अध्ययन  
– हिताक्षी गिल 5–11
3. लोकसभा चुनाव एवं मतदान व्यवहार की लोकतंत्र में भूमिका  
– विकास यादव 12–16
4. क्षेत्रीय दलों की राजनीति के संदर्भ में 18वें लोकसभा चुनाव परिणामों का राजनीतिक  
निहितार्थ  
– रमेश चौधरी 17–29
5. बिहार में नेतृत्व का संकट: लोकसभा चुनाव 2024 तथा इसके पश्चात्  
– अभिषेक नाथ 30–36
6. लोकसभा चुनाव 2024: उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वंशवाद और समाजवादी  
पार्टी  
– सुशांत यादव 37–41



निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद-विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 71वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। पाँच वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रूप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कड़ी में संश्लेषण का यह अंक शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चयता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

वर्ष 2024 को भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक चुनावी वर्ष के रूप में संबोधित किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने मतदाताओं का स्पष्ट जनादेश दिया है। चाहे उपस्थित सरकार की पुनः पुष्टि हुई हो या अन्य कोई नया प्रशासन उभरा हो, चुनावों से संदेश स्पष्ट है: मतदाताओं ने अपनी प्राथमिकताएँ व अपेक्षाएँ व्यक्त की हैं। वर्तमान सरकार के लिए, परिणाम या तो अपने पूर्व मार्ग पर चलते रहने के लिए जनादेश या नए सिरे से ध्यान व सुधार के आह्वान का संकेत देते हैं। विपक्ष के लिए, यह रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने तथा नए जोश के साथ अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के अवसर को दर्शाता है।

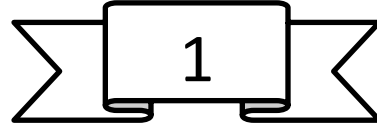
चुनाव परिणामों के उपरांत नया राजनीतिक परिदृश्य शासन में तत्काल परिवर्तन लाएगा। आर्थिक नीतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, जिसमें आधुनिक संरचनाओं के विकास, कल्याणकारी कार्यक्रमों व राजकोषीय प्रबंधन जैसी प्राथमिकताओं में संभावित परिवर्तन होंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा व रोजगार सहित सामाजिक विषयों भी नए माध्यम से परीक्षण के क्षेत्र में आएंगे। इन विषयों को प्रभावी व पारदर्शी माध्यम से संबोधित करने की प्रशासन की क्षमता जनता का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण होगी।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, परिणाम भारत के कूटनीतिक रुख व आर्थिक साझेदारी को अवश्य प्रभावित करेंगे। नेतृत्व में परिवर्तन से विदेश नीतियों को पुनः परिभाषित किया जा सकता है, जबकि निरंतरता उपस्थित अंतरराष्ट्रीय रणनीतियों को सुदृढ़ कर सकती है। जब नई सरकार

सत्ता में आती है, तो उसे जटिल घरेलू व वैश्विक विषयों का समाधान करते हुए चुनावी वादों को पूर्ण करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम मतदाताओं की आकांक्षाओं और चिंताओं का प्रतिबिंब हैं, जो उत्तरदायी व पारदर्शी शासन के महत्व को रेखांकित करते हैं।

लोकसभा चुनाव 2024 भारत की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण है। परिणाम न केवल तत्काल राजनीतिक रूपरेखा निर्धारित करेंगे अपितु आने वाले वर्षों में राष्ट्र के विकास व शासन के लिए दिशा भी निश्चित करेंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'लोकसभा चुनाव 2024: प्रदर्शन, परीक्षण एवं प्रभाव' विषय पर लेख आमंत्रित किये। छह उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ-साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।



## भारतीय चुनावी व्यवस्था: लोकसभा चुनाव 2024 का एक अध्ययन

नविता कुमारी

विधार्थी, जीसस एण्ड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

प्राचीन काल से ही लोकतंत्र का अस्तित्व भारत और विश्व के अन्य देशों में विद्यमान है। चुनाव को लोकतंत्र को कायम रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। चुनाव एक लोकतांत्रिक समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। चुनाव से ही हम अपने अधिकार का उपयोग करके अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। अतः इसके द्वारा ही हम अपने और अपने राष्ट्र के भविष्य वह विकास को चुनते हैं। आजादी के बाद से ही भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक राज्य के रूप में विद्यमान है लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि अपने राजनीतिक मत को व्यक्त करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 के मुताबिक लोकसभा चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार होना चाहिए। एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र से सभी 543 निर्वाचित सांसद को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के उपयोग से चुने जाते हैं 18वीं लोकसभा 543 सदस्यों को चुनने के लिए 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 7 चरणों में करवाए गए थे। चुनाव का परिणाम 4 जून 2024 को घोषित हुए। यह भारत के सबसे बड़े चुनाव में से एक था।

### लोकसभा चुनाव 2024: प्रदर्शन एवं परोक्षण

भारत में 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक आम चुनाव सात चरणों में हुए थे, जिसमें 543 सदस्यों का लोकसभा के लिए चुनाव किया गया था। यह 18वीं लोकसभा चुनाव था इसकी वोटों की गणना 4 जून 2024 को की गई, और परिणाम घोषित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 293 सांसदों के समर्थन की पुष्टि 7 जून 2024 को की। यह प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का तीसरा कार्यकाल है जो की एक नए इतिहास लिखने की तैयारी में है। इसी बार उन्होंने गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया था जो उनका पहला अनुभव बना। इस गठबंधन

में आंध्र प्रदेश के तेलुगू देशम पार्टी और बिहार के जनता दल मुख्य रूप से उभरे हैं सहयोगी के रूप में।

भारत एक बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है। जिसमें मुख्य रूप से दो दल उभरे हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आइएनसी) जो राजनीति पर राष्ट्रीय स्तर पर हावी रही है। भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में देश पर शासन किया। 16 जून 2024 को 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। 2019 का आम चुनाव अप्रैल मई में हुआ था। जिसमें भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी, और मोदी जी प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में भी अनुच्छेद 83 के अनुसार चुनाव का प्रावधान है। संविधान के 104 वे संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षित दो सीटों के प्रावधान को हटा दिया गया था। भारत की 1.4 बिलियन आबादी में से अधिक लोग लगभग 968 मिलियन से भी अधिक लोग वोट देने के लिए सक्षम है जो की 70% के बराबर है कुल आबादी का। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या 642 मिलियन रही और उनमें महिलाओं की संख्या 312 मिलियन थी। सबसे अधिक भागीदारी महिलाओं मतदाताओं की अब तक रही है। यह चुनाव 44 दिन तक चला था, जिसने पिछले चुनावों को पीछे छोड़ दिया है यह अब तक का सबसे बड़ा आम चुनाव था। यह भारतीय आम चुनाव 1951 से 1952 के बाद इसका दूसरा स्थान है। इस चुनाव में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों के विधानसभा चुनाव भी 2024 के आम लोकसभा चुनाव के साथ 25 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 12 विधानसभाओं में उपचुनाव के साथ करवाए गए थे।

माननीय मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल पूर्ण करके तीसरी बार के लिए चुनाव में दौड़े, उनकी पार्टी 2019 और 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ 272 सिटी प्राप्त की थी। विपक्ष में भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन इंडिया जो पहले 2023 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आई एन सी और गठबंधन है कई क्षेत्र दलों का। विपक्ष ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खराब होने, मोदी जी की भाजपा द्वारा भाषणों पर कार्रवाई न करने पर जो नफरत से भरे होते थे और चुनावों की आलोचना की गई थी और अन्य आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। भाजपा और उनके गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के जीत के लिए कई मुख्य धारा के मीडिया द्वारा जनमत सर्वेक्षणों द्वारा अनुमान लगाया गया। इसके बावजूद भाजपा ने कम सीटे ही हासिल की 2019 में 303 सीटों से घटकर 2024 में सिर्फ 240 सीटों पर ही जीत पाई और लोकसभा में बहुमत वाली एकमात्र पार्टी नहीं रही। समग्र एन डी ए सदन में 543 सीटों में से 293 सीटे प्राप्त



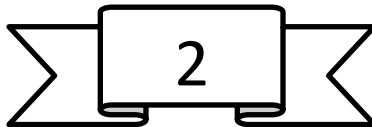
की। विपक्ष के भारत गठबंधन ने लोगों की उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन करके 234 सीटों पर जीत दर्ज की और सबसे बड़ा हिस्सा कांग्रेस का था 99 सीटों का। इसी वजह से 10 वर्षों में पहली बार आधिकारिक विपक्ष का दर्जा प्राप्त हुआ। लोकसभा में सात निर्दलीय और अन्य गैर गठबंधन के दलों के भी 10 उम्मीदवार ने भी जीत हासिल की और लोकसभा में की सीटे प्राप्त की।

मोदी जी भारत के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं ठीक पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरह। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं का मुख्य रूप से समर्थन मिला है। जो कि देश की कुल आबादी का 80% हिस्सा है। इसी वर्ग को किए गए भव्य हिंदू मंदिर बनाने का पार्टी के मुख्य वादे को पूरा कर दिया था। विपक्षी भारत गठबंधन अलग-अलग पार्टियों का गठबंधन है। जिनका कहना है कि देश की धर्मनिरपेक्षता को व लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने और किनारे वाले समूह को उच्च करने, किसानों के कीमतों में उछाल और नौकरियां युवाओं को उपलब्ध हो, इसके लिए उनकी जीत आवश्यक है। लोकसभा चुनाव 2024 में देश की जनता ने अपने अधिकार का सही प्रकार से प्रयोग किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखा विपक्ष को महत्व मिलना, भाजपा के मुकाबले में जनता के अधिकार और सजकता, जागरूकता को प्रदर्शित करता है। इस चुनाव से भाजपा का जनता के ऊपर प्रभाव में कमी देखने को मिली है। चुनाव के द्वारा लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए एक अति आवश्यक होता है। 2024 के चुनाव परिणाम ने प्रत्येक पार्टी व व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला था। इससे यह साबित हो गया है, कि आज का मतदाता एक जागरूक मतदाता है।

संदर्भ सूची:

- [https://en.m.wikipedia.org/wiki/2024\\_Indian\\_general\\_election](https://en.m.wikipedia.org/wiki/2024_Indian_general_election)
- [https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF\\_%E0%A4%86%E0%A4%AE\\_%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5,\\_2024](https://hi.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A5%80%E0%A4%AF_%E0%A4%86%E0%A4%AE_%E0%A4%9A%E0%A5%81%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%B5,_2024)
- <https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/election-results-2024-economic-justice-has-to-come-back-on-the-policy-agenda/article68250737.ece>





## लोकसभा चुनाव 2024: एक अध्ययन

हिताक्षी गिल

विद्यार्थी, जीसस एंड मैरी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

लोकसभा चुनाव 2024 भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमों में से एक है। यह चुनाव न केवल भारत की सरकार के भविष्य को निर्धारित करेगा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी डालेगा। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतियोगिता, मतदाताओं के मुद्दों पर जोर और चुनावी प्रक्रिया का परीक्षण इस चुनाव को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस चुनाव का परिणाम भारत के आगामी वर्षों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

“लोकतंत्र का पर्व चुनाव है,

जब जनता अपनी ताकत का

अहसास कराती है।”

- लोकसभा चुनाव का परिणाम

लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिख दिया है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने मजबूत प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने भी अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास किया, लेकिन वह बीजेपी को चुनौती देने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। क्षेत्रीय दलों ने अपने-अपने राज्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कुछ ने केंद्र में संभावित गठबंधन की राजनीति को प्रभावित किया। चुनावी परिणामों ने मतदाताओं की अपेक्षाओं और मुद्दों को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किया है, जिससे आने वाले वर्षों में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का दिशा-निर्देश मिलेगा।

- लोकसभा चुनाव 2024: प्रदर्शन

लोकसभा चुनाव 2024 में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी थी। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में वापसी आई। 2014 और 2019 की भारी जीत के बाद, बीजेपी अपने विकास कार्यों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दों पर जोर देते हुए चुनावी मैदान में उतरी थी। पार्टी अपने पारंपरिक मतदाताओं को संगठित करने के साथ-साथ नए वोटर्स को आकर्षित करने के लिए भी काम किया गया था।

दूसरी ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (कांग्रेस) अपनी खोई हुई साख को वापस पाने की कोशिश करती रही। राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता जनता के बीच अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को पेश किया गया। पार्टी का जोर भ्रष्टाचार विरोधी, आर्थिक असमानता, और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर रहा था। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की रणनीति अपनाई गई थी। गठबंधन की राजनीति भी 2024 के चुनाव में प्रमुख थी। एनडीए और यूपीए के अलावा, तीसरे मोर्चे की संभावना भी बनी गई थी। चुनाव के बाद सरकार गठन के लिए छोटे दलों का समर्थन महत्वपूर्ण हुआ गया था। इसलिए, सभी प्रमुख दल गठबंधन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी चुनावी रणनीति तैयार किया गया था।

चुनाव प्रचार में तकनीकी साधनों का उपयोग और युवाओं की भागीदारी इस चुनाव को और भी रोमांचक ढंग से देखा गया। सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, और वर्चुअल रैलियों का व्यापक उपयोग हुआ था। युवाओं का झुकाव और उनकी भागीदारी चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती थी। इन सभी पहलुओं का समावेश चुनाव 2024 के प्रदर्शन को रोचक और महत्वपूर्ण बना दिया था।

क्षेत्रीय दलों का प्रदर्शन भी चुनाव परिणामों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया था। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, डीएमके, और अन्य क्षेत्रीय दल अपने-अपने राज्यों में मजबूत पकड़ बनाए रखने की कोशिश करी थी। ये दल स्थानीय मुद्दों को उठाकर और अपने क्षेत्रीय वोट बैंक को मजबूत करके राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी गई थी।

“चुनाव में भाग लेना हमारा

अधिकार ही नहीं,

कर्तव्य भी है।”

- लोकसभा चुनाव 2024: परीक्षण

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए परीक्षण का मतलब चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन और विश्लेषण करना है। इसमें कई महत्वपूर्ण घटक शामिल किए गए थे।

- मतदाता पंजीकरण और जागरूकता

चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का अद्यतन, नए मतदाताओं का पंजीकरण और लोगों को मतदान के महत्व के बारे में जागरूक करते रहेना।

- ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता का परीक्षण। यह सुनिश्चित करना कि ये मशीनें सही ढंग से काम कर रही हैं और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखती थी।

- सुरक्षा प्रबंध-चुनावी आचार संहिता

चुनाव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों की तैनाती। संवेदनशील और अति-संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान और वहां विशेष सुरक्षा उपाय करते थे।

सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी आचार संहिता का पालन करना। चुनाव आयोग द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई करना।

- चुनाव प्रचार का निगरानी

चुनाव प्रचार के दौरान धन का उपयोग, फेक न्यूज, और सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले दुष्प्रचार पर नजर रखना। चुनाव आयोग द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित कर के रखना।

- चुनावी विवादों का समाधान

चुनाव के दौरान उत्पन्न होने वाले विवादों और शिकायतों का त्वरित और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करना।

अधिक से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और यह सुनिश्चित करना कि हर योग्य मतदाता अपनी आवाज उठाने के लिए प्रेरित हो।

“अच्छी सरकार चुनने के लिए

जागरूक मतदाता होना

आवश्यक है।”

- लोकसभा चुनाव 2024: प्रभाव

लोकसभा चुनाव 2024 के प्रभाव बहुआयामी होंगे और देश के विभिन्न पहलुओं पर गहरा असर डालेंगे। यहां कुछ प्रमुख प्रभावों का उल्लेख किया गया है।

- राजनीतिक परिदृश्य—आर्थिक नीतियां

चुनाव परिणाम से भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदल दिए थे। नई सरकार के गठन से नीतिगत दिशा और प्राथमिकताओं में बदलाव आ सकते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों की ताकत और उनके गठबंधन का स्वरूप भी बदल सकती थी।

चुनाव परिणाम से देश की आर्थिक नीतियों पर प्रभाव पड़ेगा। नई सरकार की आर्थिक नीतियों, बजट और सुधार योजनाओं से बाजार, निवेश और व्यापारिक माहौल प्रभावित होगा। रोजगार, महंगाई और विकास दर जैसे मुद्दों पर भी असर देखा गया था।

- सामाजिक मुद्दे अंतरराष्ट्रीय संबंध

चुनावी परिणाम का सामाजिक ताने-बाने पर भी असर पड़ेगा। सरकार की योजनाएं और नीतियां शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर क्या रुख अपनाती हैं, यह महत्वपूर्ण हुए थे।

नई सरकार के आने से भारत के अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भी बदलाव आ सकता है। विदेश नीति, व्यापारिक संबंध, और वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका पर प्रभाव पड़ा था।

- संविधान और कानून व्यवस्था—प्रादेशिक राजनीति

चुनाव के बाद संविधान और कानून व्यवस्था में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। न्यायिक सुधार, पुलिस सुधार, और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया था।

चुनाव परिणाम का प्रभाव राज्यों की राजनीति पर भी पड़ेगा। राज्यों में सरकारों के स्थायित्व, विकास योजनाओं और केंद्र-राज्य संबंधों पर इसका असर दिखने को मिला था।

➤ सामाजिक एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द

चुनाव परिणाम के बाद सामाजिक एकता और साम्प्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने की चुनौती दी गई थी। नई सरकार के नीतियों और उनके कार्यान्वयन से समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखना आवश्यक था।

➤ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन

चुनाव परिणाम का प्रभाव पर्यावरणीय नीतियों और जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्यों पर भी पड़ा गया था। नई सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्थायी विकास के लिए उठाए गए कदम महत्वपूर्ण बने थे।

➤ युवाओं और नई पीढ़ी पर प्रभाव

चुनाव परिणाम का असर युवाओं और नई पीढ़ी पर भी पड़ा था और आगे भी पड़ेगा। शिक्षा, रोजगार, और नवाचार से संबंधित नीतियों का उनके भविष्य पर सीधा प्रभाव पड़ा था।

हर वोट कीमती है,

क्योंकि हर वोट से देश का

भविष्य निर्धारित होता है।”

भारत के लोकसभा चुनाव 2024 का समापन भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाला होगा। यह चुनाव न केवल सरकार की संरचना को तय करेगा, बल्कि देश के भविष्य की नीतियों और योजनाओं को भी प्रभावित करेगा। इस चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीतियां, गठबंधन की राजनीति, और मतदाताओं के मुद्दों पर जोर देखने को मिला।

बीजेपी और कांग्रेस जैसी प्रमुख पार्टियों के अलावा, क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण भविष्य में रहेगी। मतदाताओं की बढ़ती जागरूकता और उनकी भागीदारी लोकतंत्र को और मजबूत बनाया गया था चुनाव में और आगे भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

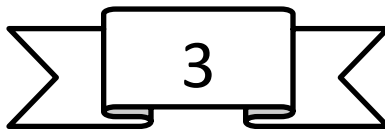
चुनाव परिणाम के बाद बनने वाली सरकार के सामने आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को संभालने की चुनौती है। नई सरकार की नीतियों का प्रभाव देश के विकास और प्रगति पर दूरगामी होती है। लोकसभा चुनाव 2024 भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो न केवल वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करेगा, बल्कि भविष्य के भारत की नींव भी रखी गई है। देश के नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और उनके निर्णय ने इस चुनाव को सार्थक बनाया है।



## संदर्भ सूची:

- लोकसभा चुनाव 2024: परिणाम और विश्लेषणत्मक more at:  
<https://hindicurrentaffairs-adda247-com/lok&sabha&election&2024&comprehensive&results&and&analysis/>
- Analysis: लोकसभा चुनाव के पहले चरण में वोटिंग ट्रेंड के क्या मायने? क्या BJP पूरा कर पाएगी मिशन 370
- 2024 आम चुनाव चरण 7 ये हैं चरण 7 में मतदान करने वाले लोकसभा क्षेत्र और राज्य
- दैनिक भास्कर— लोकसभा चुनाव
- २०२४ लोकसभा चुनाव
- <https://www-britannica-com/event/Indian&Lok&Sabha&elections&of&2024>





## लोकसभा चुनाव एवं मतदान व्यवहार की लोकतंत्र में भूमिका

विकास यादव

शोधार्थी, राजनीतिक विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत में चुनावी राजनीति एवं मतदान व्यवहार लोकतंत्र में सकारात्मक परिवर्तन लाने के रूप में देखे जाते हैं। चुनाव एवं मतदान व्यवहार शासन व्यवस्था को सुदृढ़ और परिपक्व बनाता है। इसलिए भारत में राजनीतिक दलों को समझना एवं भारत की दलीय व्यवस्था को समझना भी आवश्यक हो जाता है। भारत की चुनावी राजनीति एवं मतदान व्यवहार का मूलतः चार विभिन्न चरणों में समझा जा सकता है। पहला चरण: कांग्रेस सिस्टम (Congress system 1952–1967) के रूप में, दूसरा चरण: कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनता परिवार का गठन (Formation of Janata Parivar 1977–79), तीसरा चरण गठबंधनीय राजनीति का आना (Era of Coalitions 1989 Onwards) एवं अंतिम चरण वन डोमिनेंट पार्टी लेड सिस्टम, बीजेपी सिस्टम (One Dominant Party Led System 'BJP System' 2014 Onwards) के रूप में देखा जा सकता है। इन विभिन्न चरणों के माध्यम से भारतीय लोकसभा चुनाव एवं उसके मतदान व्यवहार की लोकतंत्र में भूमिका को समझना आवश्यक है।

पहला चरण: कांग्रेस सिस्टम (Congress system 1952–1967): भारतीय राजनीति के प्रथम चरण का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा जिसमें की वह सभी राज्यों के चुनावों में एवं लोकसभा चुनावों में विजय रही। इसी अनुसार विभिन्न लेखकों ने इस चरण को अपने अनुसार परिभाषित किया है। जैसे कि रजनी कोठारी (Rajni Kothari) उन्होंने इस चरण को वन पार्टी डोमिनेन्स सिस्टम (One Party Dominance System) यानी कांग्रेस सिस्टम के रूप में कहा, मोरिस जॉन्स (Morris Jones) ने इसे वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम (One Party Dominant System) कहा, जियोवानी सार्टोरी (Giovanni Sartori) ने इस चरण को प्री डोमिनेंट पार्टी सिस्टम (Pre – Dominant Party System) कहा। इस चरण को पॉलिटिक्स ऑफ एलाइनमेंट (Politics of Alignment) के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है क्योंकि मतदाता अपनी पसंद

की प्रमुख पार्टी से वैचारिक रूप से जुड़े थे। अगर इस चरण के मतदान व्यवहार का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है की फ्लोटिंग वोटर्स (Floating Voters) को इस चरण में चिन्हित किया जा सकता है। यह वह मतदाता होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए होते हैं एवं यह अपनी मतदान प्रक्रिया स्वतंत्र रखते हुए चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं, अतः इनका मतदान व्यवहार फ्रीबीज (Freebies) एवं नीतियों (Policies) को देखते हुए समय-समय पर परिवर्तित होता नजर आता है। इस चरण के अंतिम दौर में मतदाताओं के मध्य असंतोष सा नजर आया जिसके कारण 1967 में कांग्रेस पार्टी पहली बार चुनावी परिणामों में विभिन्न राज्यों में कमजोर नजर आयी एवं मतदाताओं ने नये राजनीतिक विकल्पों की ओर रुख किया।

दूसरा चरण: जनता परिवार का गठन (Formation of Janata Parivar 1977-79): भारतीय राजनीति दूसरे चरण में दो दलीय प्रणाली की ओर अग्रसर हुई इसमें जनता परिवार का गठन एवं उत्थान देखा गया। कांग्रेस के समक्ष गैर-कांग्रेसी दलों का इस चरण में उद्भव देखा गया जिसमें जयप्रकाश नारायण का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अतः इस चरण में कांग्रेस पार्टी के वर्चस्व को विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुनौती दी गई, जिसमें की जनता परिवार के पांच महत्वपूर्ण घटकों के रूप में राजनीतिक दलों को देखा जा सकता है, कांग्रेस ओ (Congress O) का प्रतिनिधित्व मोरारजी देसाई द्वारा, जनसंघ (Jana Sangh) का प्रतिनिधित्व अटल बिहारी वाजपेई एवं लालकृष्ण आडवाणी द्वारा, सोशलिस्ट पार्टी (Socialist Party) का प्रतिनिधित्व राज नारायण एवं जॉर्ज फर्नांडिस के द्वारा, भारतीय लोकदल (Bharatiya Lok Dal) का प्रतिनिधित्व चौधरी चरण सिंह के द्वारा, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी (बदहतमे वित कमउवबतंबल) का प्रतिनिधित्व बाबू जगजीवन राम द्वारा किया गया। इस चरण को पॉलिटिक्स ऑफ डी-एलाइनमेंट (Politics of De-Alignment) के रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें की मतदाताओं की बदलती प्रवृत्ति को चिन्हित किया जा सकता है। मतदाताओं ने एक विकल्प के रूप में जनता परिवार को इस दौरान स्वीकृत किया एवं पहली बार कांग्रेस पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। मतदाताओं द्वारा पारंपरिक दलों को छोड़कर नए दलों की ओर जाते हुए इस चरण में देखा गया। हालांकि जनता परिवार एक विकल्प के रूप में भारतीय राजनीति में ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाया एवं वह वैकल्पिक राजनीति को परिपक्व नहीं रख पाया।

तीसरा चरण: गठबंधनीय राजनीति का काल (Era of Coalitions 1989 Onwards): तीसरे चरण की भारतीय राजनीति को गठबंधनानिया राजनीति के तौर पर देखा जा सकता है जिसमें की राज्य दलों एवं राष्ट्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में अत्यधिक सहभागिता देखी जा सकती है। इस चरण में गठबंधन के रूप वी. पी. सिंह की सरकार, जिसे नेशनल फ्रंट के रूप में जाना जाता है, उसके पश्चात चंद्रशेखर का आना, फिर नरसिम्हा राव की सरकार, 1996-97 में देवेगौड़ा एवं आई के गुजराल के प्रतिनिधित्व में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट का आना, 1998-1998 में अटल बिहारी वाजपेई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण विकास गठबंधनिय राजनीति के दौर में 1999 में नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस (National Democratic Alliance) के रूप में एवं 2004 में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एलायंस (United Progressive Alliance) के रूप में देखा गया। अगर इस चरण के मतदान व्यवहार की बात करें तो इस चरण में ड5 फिनोमना बहुत महत्वपूर्ण रहा जिसको की मंडल, मंदिर, मस्जिद, मार्केट, एवं मतदाता के रूप में परिभाषित किया गया। इस चरण में मतदाताओं के मतदान व्यवहार में एक नवीन परिवर्तन देखा गया जो की री-एलाइनमेंट आफ वोटर्स (Re-Alignment) के रूप में देखा जा सकता है।

अंतिम चरण: वन डोमिनेंट पार्टी लेड सिस्टम, बीजेपी सिस्टम (One Dominant Party Led System] 'BJP System' 2014 Onwards): भारतीय राजनीति का यह चरण ऐतिहासिक रूप में एक नए दृष्टिकोण एवं नए व नवीन परिवर्तनों को दर्शाता है। भारतीय राजनीति में पहली बार कोई राजनीतिक दल भारी बहुमत से सरकार का गठन करता है, जिसमें की देखा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2014 लोकसभा चुनाव में एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में सरकार का गठन करती है। इस चरण में मतदान व्यवहार का अधिक बल गुड गवर्नेंस की और ज्यादा अग्रसर रहा जिसमें की फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिला मतदाता एवं युवा मतदाता एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुए एवं लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नजर आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो इस चरण में देखी गई वह साइलेंट वोटर्स (Silent Voters) के रूप में देखी गई। यह वह मतदाता होते हैं जो राजनीतिक परिणामों को एक नवीन मोड़ देते हुए नजर आते हैं। ये मतदाता मुखर ना होकर अपने मत का प्रयोग करते हैं एवं लोकतंत्र में इनकी निर्णायक भूमिका पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक देखी गई है।

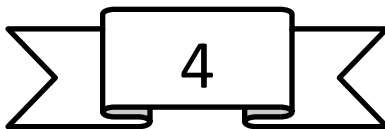
अंततः यह कहा जा सकता है की भारतीय राजनीति नवीन परिवर्तनों एवं सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आती है। इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका मतदाताओं की है जो कि

समय-समय पर चुनावी प्रणाली में अपनी सहभागिता दर्शाते हुए नवीन परिवर्तनों को लेकर आते हैं। राजनीतिक दल भी नीतियों एवं कार्यों द्वारा नए परिवर्तनों पर बल देते हुए अपना योगदान लोकतंत्र को और मजबूत एवं सुदृढ़ करते नजर आते हैं। इसलिए भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदाता राष्ट्रीय निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं जो की किसी भी लोकतंत्र के लिए सकारात्मक का प्रतीक एवं प्रतिबिंब है।

संदर्भ सूची:

- Kothari, R. (1970). *Politics in India*. New Delhi: Orient Longman
- Kothari, R. (1989). "The Congress System in India" in Rajni Kothari, *Politics and the People in Search of a Humane India*. Vol. 1. India: Ajanta Publications.
- Sunil K Choudhary. (2024). *India@75: A Changing Electoral Democracy*. New Delhi: Aakar Books





## क्षेत्रीय दलों की राजनीति के संदर्भ में 18वें लोकसभा चुनाव परिणामों का राजनीतिक निहितार्थ

रमेश चौधरी

शोधार्थी, अफ्रीकी अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनावों के जनादेश में, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है। मौजूदा सरकार की इस चुनावी उपलब्धि के बावजूद, ये चुनाव परिणाम भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण संक्रमण को दर्शाते हैं, जिसमें विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने मजबूत प्रदर्शन किया है। भाजपा ने स्वयं 240 सीटें प्राप्त की हैं, जो कि उसकी अपनी और कई चुनावी सर्वेक्षण एजेंसियों की अपेक्षा से काफी कम है। दूसरी ओर, इंडिया ब्लॉक ने अप्रत्याशित रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की विभिन्न क्षेत्रीय पार्टियों ने संयुक्त रूप से 234 सीटें हासिल की हैं। इन लोकसभा चुनावों में क्षेत्रीय दलों का चुनावी उदय राजनीतिक रूप से सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण पहलू है। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का अच्छा चुनावी प्रदर्शन इंडिया ब्लॉक की चुनावी सफलता का प्रमुख कारक है।

लोकसभा चुनावों में भाजपा के सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बावजूद, एनडीए सरकार की स्थिरता दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों दृ बिहार से नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) और आंध्र प्रदेश से एन चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के समर्थन पर निर्भर है। विपक्षी मोर्चे पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी विपक्षी इकाई के रूप में उभरी है, जिसने पिछले दो लोकसभा चुनावों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। हालांकि, इन लोकसभा चुनावों में विपक्षी मोर्चे के लिए क्षेत्रीय दलों जैसे समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की उल्लेखनीय सफलताओं को श्रेय देना आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में तेलुगू देशम पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय लोक दल, जनता दल (सेक्युलर), जन सेना पार्टी और अन्य प्रमुख गठबंधन सहयोगी हैं और इस चुनाव में उन्होंने अपने-अपने राज्यों में अच्छा प्रदर्शन किया है। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया ब्लॉक) में समाजवादी पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार), राष्ट्रीय जनता दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय दल गठबंधन सहयोगी हैं और इस लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने-अपने राज्यों में अपनी राजनीतिक जमीन और जनाधार वापस प्राप्त किया है। सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों का यह गठबंधन क्षेत्रीय दलों के निरंतर प्रभाव और भविष्य के राजनीतिक मामलों व विमर्श को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

18वें लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का उदय

2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तेजी से बढ़ती सफलता और उदय ने क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय राजनीति के हाशिये पर धकेल दिया था, जो पिछले कई दशकों के दलीय राजनीतिक प्रवृत्ति से अत्यंत भिन्न था। परंतु 2024 के लोकसभा चुनावों के जनादेश और क्षेत्रीय दलों का उदय भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक परिवर्तन का प्रमाण है। भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 293 सीटें हासिल कीं। इसके विपरीत विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल कीं। 2024 के लोकसभा चुनावों में, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एससीपी), शिवसेना (यूबीटी), जेडीयू और एलजेपी (रामविलास) क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक और चुनावी दृष्टि से उदय हुआ है।

समाजवादी पार्टी (SP) – उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसने कुल 80 सीटों में से 37 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने लोकसभा चुनाव के इतिहास में अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज किया है। समाजवादी पार्टी देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरा है और यह राष्ट्रीय स्तर 18वीं लोकसभा का तीसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जो इस लोकसभा में समाजवादी पार्टी के उत्थान और महत्व को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी के चुनावी पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण तत्व सामाजिक समतावाद की



विचारधारा और संविधान को बचाने की प्रतिज्ञा पर जोर देना था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक व चुनावी झटका रहा और इंडिया ब्लॉक के लिए एक बड़ा सकारात्मक पहलू रहा है।

तेलुगू देशम पार्टी (TDP)– एन. चंद्रबाबू नायडू की तेलुगू देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश राज्य के लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में से 16 सीटें जीतकर शानदार जीत दर्ज की। इस चुनाव में तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) ने भाजपा और प्रसिद्ध तेलगु फिल्म अभिनेता पवन कल्याण द्वारा नेतृत्व जन सेना पार्टी के साथ गठबंधन किया और टीडीपी के नेतृत्व में एनडीए ने आंध्र प्रदेश में शानदार जीत दर्ज की। तेलुगू देशम पार्टी ने आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की और चंद्रबाबू नायडू राज्य के मुख्यमंत्री बने। आंध्र प्रदेश की राजनीति में तेलुगू देशम पार्टी के उदय के प्रमुख कारक भाजपा और जन सेना पार्टी के साथ उचित राजनीतिक गठबंधन, जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर और इस चुनाव में टीडीपी के सुपर सिक्स लोकलुभावन वादे जैसे बुजुर्ग महिलाओं के लिए मासिक पेंशन, महिलाओं के राज्य परिवहन बसों में मुफ्त यात्रा, बेरोजगारी भत्ता और किसानों के लिए नकद सहायता हैं।

अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) – पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने भाजपा के आक्रामक चुनाव अभियान का डटकर सामना किया। भ्रष्टाचार के आरोपों और केंद्र सरकार की एजेंसियों केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को जेल में डालने सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने के बावजूद, ममता बनर्जी भाजपा की बढ़त को रोकने और पश्चिम बंगाल में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहीं। मुस्लिम अल्पसंख्यक मतदाताओं और राज्य सरकार की सामाजिक योजनाओं जैसे लक्ष्मी भंडार और कन्याश्री योजना के प्रत्यक्ष लाभार्थियों के समर्थन ने टीएमसी की बढ़त में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ गठबंधन के बिना अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है और टीएमसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बाद भारत ब्लॉक में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है।

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)– एमके स्टालिन की द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने इस लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु की कुल 39 संसदीय सीटों में से सबसे अधिक 22 सीटें जीतीं। डीएमके का इन

लोकसभा चुनावों में राजनीतिक दल के तौर पर सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा, डीएमके ने तमिलनाडु में जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा उन सभी पर जीत हासिल की। तमिलनाडु की राजनीति में विभाजित विपक्ष, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की मृत्यु के बाद अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईडीएमके) में नेतृत्व संकट और डीएमके गठबंधन का एनडीए विरोधी अभियान जो भाजपा द्वारा विभाजनकारी-सांप्रदायिक राजनीति के आरोपों पर केंद्रित रहा, इन कारकों ने तमिलनाडु में डीएमके नीत गठबंधन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डीएमके एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक दल रहा जिसने इंडिया ब्लॉक की सीट हिस्सेदारी में आवश्यक योगदान दिया।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) (Shivsena – UBT) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) (NCP & SCP) – शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने महाराष्ट्र राज्य में क्रमशः नौ और आठ लोकसभा सीटें जीतीं। मूल शिवसेना में वर्तमान महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और एनसीपी में वर्तमान उप- मुख्यमंत्री अजीत पवार के फूट के पश्चात् शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (एससीपी) के राजनीतिक पुनर्गठन के बावजूद, उनके संबंधित मूल दलों में गुटबाजी के बाद, दोनों महाराष्ट्र आधारित क्षेत्रीय दलों ने इस चुनाव को अविश्वसनीय रूप से अच्छे तरीके से लड़ा और इस लोकसभा में अपनी राजनीतिक विरासत को पुनर्जीवित और प्राप्त किया। कठिन चुनौतियों के बावजूद, उद्धव ठाकरे विजयी हुए, जिससे उनकी छवि उत्साही और करिश्माई नेता के रूप में मजबूत हुई। शरद पवार ने भी अजोत पवार के खिलाफ अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित की और इस लोकसभा चुनाव में अपना व्यापक समर्थन और आधार हासिल किया। यद्यपि उनकी लोकसभा सीटों की संख्या महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा नहीं रही, लेकिन उन्होंने सत्तारूढ़ एनडीए के विरुद्ध इंडिया ब्लॉक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जनता दल (यूनाइटेड) (JDU) और लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) (LJP – Ramvila) दृ इस लोकसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) ने 12 सीटें जीतीं, जो बिहार राज्य में भाजपा की जीत की सीटों की बराबरी कर गई। जेडी(यू) 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी लड़ी गई 16 में से 12 सीटों पर जीत हासिल की है। जेडी(यू) का यह राजनीतिक उदय नीतीश कुमार को एनडीए सरकार के इस कार्यकाल में पर्याप्त राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिहार के क्षेत्रीय नेता और दल का तेजी से इस लोकसभा चुनाव उदय हुआ है, वे हैं लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान। चिराग

पासवान की पार्टी एलजेपी (रामविलास) ने बिहार की 5 में से 5 सीटें जीतीं, जो उनकी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर लड़ी थीं। चिराग पासवान की उपलब्धि विशेष रूप से उनकी पार्टी के भीतर पिछले विभाजन को देखते हुए उल्लेखनीय है, जिसका नेतृत्व उनके चाचा पूर्व केन्द्रीय मंत्री पशुपति पारस ने किया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पार्टी का आधिकारिक नाम और चुनाव चिन्ह खो दिया गया था।

18वें लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का पतन

2024 के लोकसभा चुनावों में कई उल्लेखनीय क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों और क्षत्रपों का पतन भी देखने को मिला। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (BJD), जिसने दो दशकों से अधिक समय तक ओडिशा में राजनीतिक और चुनावी रूप से दबदबा बनाए रखा था, बीजेडी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने ओडिशा राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में जीत हासिल की। इसी तरह, बहुजन समाज पार्टी, भारत राष्ट्र समिति, वाईएसआरसीपी, एआईएडीएमके और शिरोमणि अकाली दल को इन लोकसभा चुनावों में चुनावी रूप से भारी चुनावी असफलताओं का सामना करना पड़ा।

बहुजन समाज पार्टी (BSP)— वरिष्ठ दलित नेत्री और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को इस लोकसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक झटका लगा है क्योंकि वह लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोलने में विफल रही है। मायावती की पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती थीं। बसपा के पतन का प्रमुख कारण विपक्षी राजनीति के प्रति मायावती का उदासीन रुख और बसपा के पारंपरिक जाटव दलित वोट आधार में परिवर्तन ने बसपा को राजनीतिक परिदृश्य में एक कमजोर राजनीतिक विकल्प के रूप में पेश किया है। उत्तर प्रदेश में बसपा के राजनीतिक महत्व में गिरावट का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण उत्तर प्रदेश में दलित युवा नेता के रूप में चंद्रशेखर आजाद का उभरना है।

बीजू जनता दल (BJD)— ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की बीजू जनता दल (बीजेडी) एक और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय पार्टी है, जिसे 2024 के लोकसभा और ओडिशा में राज्य विधानसभा चुनावों में बड़ा झटका लगा है। भाजपा ने राज्य विधानसभा में पूर्ण बहुमत हासिल करके राज्य में नवीन पटनायक के 24 साल के शासन को समाप्त कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनावों में, बीजेडी को एक भी सीट नहीं मिली।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSR Congress Party)— आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (YSRCP), जो 2019 से आंध्र प्रदेश पर शासन कर रही थी, ने 2024 के लोकसभा चुनावों में राज्य की 25 लोकसभा सीटों में से सिर्फ चार पर जीत हासिल की। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा चुनाव तेलुगु देशम पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन से भारी हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की हार के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारक राज्य में रोजगार और विकास की समस्या, प्रशासन का अहंकार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, जनता से जगन मोहन रेड्डी का संपर्क टूटना, नेतृत्व संकट और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के प्रति जगन मोहन रेड्डी की प्रतिशोध की भावना प्रमुख हैं।

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIDMK)— अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) तमिलनाडु में 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार गई, क्योंकि उन्हें इन चुनावों में कोई सीट नहीं मिली। इससे पहले अन्नाद्रमुक ने 2019 के लोकसभा चुनावों में केवल एक सीट जीती थी। अन्नाद्रमुक के चुनावी पतन का प्रमुख कारण जयललिता के निधन के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व के लिए संघर्ष रहा। वे 2021 में एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके से राज्य विधानसभा चुनाव भी हार गए।

भारत राष्ट्र समिति (BRS)— तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति, जो तेलंगाना में पहली बार विधानसभा चुनाव में विजयी हुई थी, ने राज्य में लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। इस लोकसभा चुनाव में वे राज्य में एक भी सीट नहीं जीत पाए। कुछ महीने पहले बीआरएस 2023 में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस के हाथों राज्य विधानसभा चुनाव भी हार गई थी। इन चुनावों में बीआरएस की चुनावी गिरावट का सबसे प्रमुख कारण तेलंगाना में भाजपा का उदय और बढ़त है।

शिरोमणि अकाली दल (SAD)— शिरोमणि अकाली दल, जिसने कई बार पंजाब पर शासन किया और राज्य की राजनीति में प्रमुख स्थान रखता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में अकाली दल को पंजाब में एक सीट मिली है, जबकि 2019 में उसे दो सीटें मिली थीं। भारत की दूसरी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी शिरोमणि अकाली दल, भाजपा के साथ गठबंधन टूटने के बाद अभी तक खुद को फिर से संगठित नहीं कर पाई है। अकाली दल के पतन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक

यही है कि उनका एक राजनीतिक दल के रूप में राजनीतिक दृष्टि से असंगठित और अव्यवस्थित हैं।

ये छह प्रमुख क्षेत्रीय दल थे जिन्होंने राज्य सरकारें चलाई थीं और लोकसभा चुनावों में महत्वपूर्ण प्रासंगिकता रखते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों में उन्हें काफी नुकसान हुआ। ये मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक क्षत्रप हैं जिन्होंने अतीत में राज्य सरकारें बनाई हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन (एनडीए या इंडिया ब्लॉक) के साथ गठबंधन नहीं किया, और लगभग शून्य सीटों पर पहुंच गए हैं। यह स्पष्ट रूप से एक राष्ट्रीय चुनाव था जहां लोगों ने एनडीए या इंडिया ब्लॉक के लिए मतदान किया।

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर क्षेत्रीय दलों के उदय का निहितार्थ

चूंकि कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपनी चुनावी सफलता से राष्ट्रीय राजनीति और दलीय व्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को इन निर्णायक क्षेत्रीय ताकतों और क्षत्रपों को समायोजित करने के लिए अनुकूल होना चाहिए। इसलिए, 2024 के लोकसभा चुनाव न केवल क्षेत्रीय दलों के महत्व की पुष्टि करते हैं, अपितु आने वाले वर्षों में एक अधिक जटिल और बहुआयामी राजनीतिक क्षेत्र का भी संकेत देते हैं।

1- गठबंधन राजनीति का नया युग

ये लोकसभा चुनाव परिणाम एक दशक के पश्चात् भारतीय राजनीति में एक आदर्श बदलाव का संकेत देते हैं जो एक नए गठबंधन युग की शुरुआत को चिह्नित करता है, जहां राष्ट्रीय दलों के नेतृत्व वाले गठबंधन जिसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं, इन सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन में तेजी से प्रमुख होते जा रहे हैं। इस प्रकार यह राष्ट्रीय दलों के घटते एकल प्रभुत्व और देश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करता है।

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के बहुमत में कमी आई है, तथा उसे 293 सीटें प्राप्त हुई हैं, जबकि भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया ब्लॉक) को 234 सीटों के साथ महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। भाजपा की एकल बढ़त बहुमत के 272 के आंकड़े से कम है, जो सरकार बनाने के लिए गठबंधन सहयोगियों पर निर्भरता को दर्शाता है।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इस समय भारत की विपक्षी राजनीति में एक केंद्रीय स्तंभ है, ने 2019 में अपनी संख्या को दोगुना करके अच्छी वापसी की है और 99 सीटें जीती हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय राजनीतिक ताकतों ने अपनी जमीन बरकरार रखी है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ बढ़त भी हासिल की है। इसलिए ये नतीजे विपक्षी गठबंधन समीकरण में क्षेत्रीय दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करते हैं।

इस चुनाव से ये भी ज्ञात होता है कि मतदाता राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रभुत्व की द्विआधारी व्यवस्था से आगे बढ़ रहे हैं, और अधिक स्थानीय व मुद्दा आधारित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम भारतीय राजनीति के क्षेत्रीय आयामों स्पष्ट संकेतक हैं, जहाँ क्षेत्रीय दल न केवल गठबंधन सहयोगी हैं, यद्यपि गठबंधन की राजनीति में नेता और रणनीतिकार भी हैं। यह परिवर्तन भारत की जनता की विविध आकांक्षाओं को दर्शाते हुए अधिक समावेशी और प्रतिनिधि शासन की शुरुआत कर सकता है।

## 2- राष्ट्रीय नीतियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मध्य संतुलन व सामंजस्य

2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी संक्रमण आया है, जिसने राष्ट्रीय सरकार और दलीय राजनीति को आकार देने में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर किया है। यह परिदृश्य नीतीश कुमार और एन. चंद्रबाबू नायडू जैसे क्षेत्रीय नेताओं को एनडीए की राजनीति में अपरिहार्य राजनीतिक मोर्चे के रूप में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचता है। उनका प्रभाव न केवल उनकी चुनावी सफलता का बल्कि मतदाताओं की भावना का भी प्रमाण है जो राष्ट्रीय नीतियों और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मध्य संतुलन चाहता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के बाद भाजपा मुख्यालय में अपने विजयी संबोधन में बिहार और आंध्र प्रदेश में एनडीए के अच्छे प्रदर्शन में नीतीश कुमार और एन. चंद्रबाबू नायडू के महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार किया। यह स्वीकारोक्ति भारतीय राजनीति के उभरते क्षेत्रीय आयामों को दर्शाती है, जहाँ क्षेत्रीय आवाजें अब केवल प्रतिध्वनि नहीं हैं, बल्कि भारतीय दलीय लोकतंत्र का केंद्र हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन क्षेत्रीय ताकतों का चुनावी पुनरुत्थान एक परिपक्व मतदाता वर्ग का उद्भव दर्शाता है जो स्थानीय मुद्दों और शासन को प्राथमिकता देता है जबकि अभी भी

व्यापक राष्ट्रीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ संरेखित है। जेडी(यू) और टीडीपी की यह रणनीतिक राजनीतिक स्थिति, उनके गठबंधन सहयोगियों के बदलाव के इतिहास के साथ मिलकर, उन्हें अद्वितीय लाभ प्रदान करती है। उन्होंने क्षेत्रीय हितों को सुरक्षित करने और राष्ट्रीय सरकार में अपनी भूमिका को पुख्ता करने के लिए इसका कुशलतापूर्वक उपयोग किया है। जैसे-जैसे भारतीय चुनावी राजनीति आगे बढ़ती है, राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का एकीकरण किसी भी सरकार के लिए आवश्यक होगा जो एक स्थिर और समावेशी जनादेश हासिल करने की आकांक्षा रखती है।

3- राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकताओं और मुद्दों का महत्त्व

चूंकि क्षेत्रीय दल इस लोकसभा चुनाव में निर्णायक घटक के रूप में उभरे हैं। राष्ट्रीय राजनीति में अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित करने और अभूतपूर्व स्पष्टता के साथ क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को बनाए रखने के कारण, अंतिम परिणाम भारतीय राजनीति में एक परिवर्तनकारी बदलाव को रेखांकित करता है। गठबंधन की राजनीति में स्थानीय चिंताएँ और प्राथमिकताएँ केंद्र में आ जाती हैं और राष्ट्रीय मुद्दों के प्रभुत्व को चुनौती देती हैं। क्षेत्रीय दलों की अपने-अपने राज्यों में गहरी पैठ है, उन्होंने अपने मतदाताओं को सीधे प्रभावित करने वाले मुद्दों पर जोरदार प्रचार किया है। क्षेत्रीय दलों ने अपने घोषणापत्रों को अपने मतदाताओं की आकांक्षाओं और शिकायतों को प्रतिबिंबित करने के लिए तैयार किया।

उनकी चुनावी सफलता का श्रेय क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक बारीकियों के साथ तालमेल बिठाने की उनकी राजनीतिक क्षमता को दिया जा सकता है। क्षेत्रीय स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करके और अधिक विकेन्द्रीकरण की वकालत करके, वे एक महत्वपूर्ण जनादेश हासिल करने में सफल रहे जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रीय राजनीति में उनकी पर्याप्त उपस्थिति में परिवर्तित हो गया।

इस चुनाव के परिणाम से भारतीय राजनीति संघवाद के प्रति अधिक अनुकूल हो गई है, जिसमें मतदाताओं ने उन दलों का समर्थन किया है जिन्होंने व्यापक एक समान समाधानों पर क्षेत्रीय विकास को प्राथमिकता देने का वादा किया था। यह परिणाम भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण है, जहाँ शासन में विविधता को सभी हितधारकों द्वारा स्वीकार किया जाता है। 2014 के बाद से, भारत में लोकसभा चुनावों में अक्सर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हावी रहे हैं। हालाँकि, 2024

के लोकसभा चुनाव ने इस प्रवृत्ति से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को चिह्नित किया है, जिसमें क्षेत्रीय दल प्रभावी रूप से क्षेत्रीय मुद्दों को बरकरार रखते हुए उन्हें प्राथमिकता दे रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना अभियान केवल केंद्र सरकार की आलोचना करने के बजाय सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की बेरोजगारी और खराब शासन व्यवस्था पर केंद्रित किया। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी ने अपना अभियान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार के कथित भ्रष्टाचार और सरकारी धन के कुप्रबंधन पर केंद्रित किया। इसी तरह, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा बंगाल की उपेक्षा पर एक शक्तिशाली अभियान चलाया। ममता बनर्जी के अभियान ने क्षेत्रीय असमानताओं और अधिक राज्य स्वायत्तता की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिसने मतदाताओं को प्रभावित किया। यह क्षेत्रीय राजनीतिक प्राथमिकताएं मतदाताओं के साथ चुनावी रूप से प्रतिध्वनित हुईं, जिससे स्थानीय चिंताओं और प्राथमिकताओं के साथ क्षेत्रीय दलों का राजनीतिक संरेखण प्रदर्शित हुआ।

ये उदाहरण स्पष्ट हैं कि कैसे क्षेत्रीय दलों ने 2024 के चुनाव को क्षेत्रीय मुद्दों के मंच में सफलतापूर्वक परिवर्तित कर दिया। ऐसा करके, उन्होंने न केवल क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को बरकरार रखा, बल्कि चुनावी परिदृश्य को भी परिष्कृत किया जिससे भारत के लोकतंत्र में स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया। यह बदलाव एक परिपक्व राजनीतिक माहौल को दर्शाता है जहाँ क्षेत्रीय आवाजें राष्ट्रीय राजनीतिक विमर्श का अभिन्न अंग हैं।

#### 4- क्षेत्रीय दलों के उदय से केन्द्र-राज्य संबंधों में संभावित परिवर्तन

राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों के पुनः उभरने से केंद्र और राज्य सरकार के मध्य संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। इस पहलू में दोनों तरह की संभावनाएं संभव हैं, इससे केंद्र और राज्य सरकार के मध्य अधिक टकराव हो सकता है या इसे सकारात्मक विकास के रूप में देखा जा सकता है और देश के समावेशी विकास के अनुरूप भी देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में सौहार्दपूर्ण तरीके से शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से "टीम इंडिया" के रूप में मिलकर काम करने का आह्वान किया था। नीति आयोग की स्थापना का एक प्रमुख उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। इन शुरुआती प्रयासों के बावजूद मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों, विशेषकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मध्य समय-समय पर



टकराव देखा गया है। इस टकराव से जुड़ी प्रमुख परिधि वित्तीय और राजकोषीय संबंध हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्य सरकारों ने बार-बार केंद्र पर कथित रूप से धन रोकने का आरोप लगाया है।

इस लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों के उदय के बाद से, राज्य सरकारों के पास अब अधिक राजनीतिक सौदेबाजी की शक्ति होगी। एनडीए सरकार के दो प्रमुख सहयोगी हैं, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी और बिहार में जनता दल (यूनाइटेड)। वे केंद्र-राज्य राजकोषीय और वित्तीय मामलों पर आगे की चर्चा के लिए वास्तव में उत्सुक होंगे। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार का भी मानना था कि एनडीए में टीडीपी की महत्वपूर्ण संख्या टीडीपी को विशेष राज्य का दर्जा देने की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग के लिए केंद्र से अधिक ध्यान आकर्षित करने में मदद कर सकती है। साथ ही, राजीव कुमार ने कहा कि चूंकि भाजपा के लिए संख्या पिछले कार्यकाल की तरह मजबूत नहीं है, और राज्यों के पास अधिक सौदेबाजी की शक्ति होने के कारण, केंद्र-राज्य संबंध सकारात्मक मोड़ भी ले सकते हैं, ज्यादातर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के मामले में।

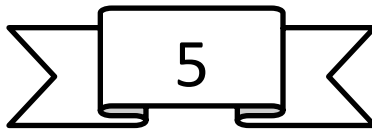
निष्कर्ष के तौर पर, 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय राजनीति के उभरते आयाम व परिवर्तन का स्पष्ट संकेत हैं, जहाँ जनता दल (यूनाइटेड), तेलुगु देशम पार्टी, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियाँ सिर्फ गठबंधन सहयोगी नहीं हैं, बल्कि गठबंधन की राजनीति में नेता व धुरी भी हैं। यह परिवर्तन भारत की जनता की विविध आकांक्षाओं को दर्शाते हुए अधिक समावेशी और प्रतिनिधि शासन की शुरुआत कर सकता है। इस परिवर्तन ने भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों और क्षेत्रवाद के स्थायी महत्व को रेखांकित किया।

## संदर्भ सूची:

- Alam, A. (2024). *Why Andhra Pradesh voters turned against Jagan Mohan Reddy and YSRCP*. The Indian express
- Banerjee, S. (2024). *MVA turnaround gives jolt to BJP-Shinde-led Mahayuti in Maharashtra*. The Hindu
- Chaturvedi, R.M. (2024). *Abki baar coalition sarkar: India delivers a fractured mandate that will require the BJP to seek the help of NDA allies*. The Economic Times
- Dasgupta, M. (2024). *In a major setback to BJP in West Bengal, Mamta Banerjee -led TMC set to increase seats*. The Hindu Business Line
- Iyer, P.V. (2024). *Lok Sabha Election Results 2024: Decoding the Verdict* The Indian Express
- Kamran, S. (2024). *The resurgence of the Samajwadi party*. The Hindu
- Kumar, A. (2024). *From obscurity to a 'Kingmaker': Tracing Chandrababu Naidu's Politics*. Business Standard
- Mishra, A. (2024). *Two Kingmakers emerge*. Frontline
- Minhaz, A. (2024). *How BRS, the party that created Telangana, is touted in its own state*. Frontline
- Ozarkar, V. (2024). *Uddhav Thackeray orchestrates Shiv Sena's remarkable revival in Lok Sabha Polls*. The Indian Express

- Pimpalkhare, M & Baruah, R. (2024). *Lok Sabha Elections 2024: Return of Regional Parties may smoothen Centre–State relations*. Livemint
- Ranjan, A. (2024). “Rise of the Regionals: How Regional Parties Tipped the Scales against BJP Dominance”. Frontline
- Rai, D. (2024). *Lok Sabha 2024: Shifts and retentions in strongholds*. India Today
- Sharma, A. (2024). *Is it the end of the road for the Akali Dal?*. Frontline
- Team TOI. (2024). *40-40: Tamil Nadu voters give it all to DMK alliance*. The Times of India
- Tewary, A. (2024). *Bihar Political parties begin reflecting on electoral performance in 2024 Lok Sabha elections*. The Hindu
- Verma. L. (2024). *Null and Void: The Fall and Fall of Mayawati’s BJP*. The Indian express.
- Wyatt, A. (2024). *Political Pluralisms: India’s Party Politics Deliver Uneasy win for BJP*. THC





## बिहार में नेतृत्व का संकट: लोकसभा चुनाव 2024 तथा इसके पश्चात्

डॉ. अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, एम.एल.टी. कॉलेज, सहरसा

भारतीय राजनीति में यह एक लगभग सिद्ध सूत्र है कि प्रधानमंत्री पद का मार्ग उत्तरप्रदेश और बिहार से होकर गुजरता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो राजनीतिक दल बिहार और उत्तरप्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती है उसकी लोकसभा में सीटों की संख्या अधिक होती है, और उसी दल का प्रधानमंत्री बनने की सम्भावना भी रहती है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री के विजय रथ के अपने अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर पाने का सीधा सम्बन्ध उपरोक्त गणित से है। इस आलेख का उद्देश्य लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की समीक्षा और विश्लेषण बिहार प्रान्त के सन्दर्भ में करने की है। साथ ही कुछ उभरती प्रवृत्तियों को भी पहचानने और विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। इस आलेख को लिखने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव परिणामों, समाचारपत्रों की रिपोर्ट और लेखक की आधारिक स्तर पर चुनावी विश्लेषण के अनुभव का प्रयोग किया गया है।

यह कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनमानस अपने वोट का प्रयोग इस समझदारी से करती है कि चुनावी विश्लेषकों और चुनाव पूर्व तथा पश्चात के अनुमानों को गलत सिद्ध कर चुनौती प्रस्तुत करती रहती है। वर्तमान चुनाव भी इस सन्दर्भ में याद रखा जायेगा कि कैसे 400 सीटों का दावा करने वाली पार्टी सामान्य बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाई। अन्यथा हम वर्तमान सत्ताशील दल के पिछले चुनाव प्रदर्शनों को बिहार के दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं और उपरोक्त गणित की समीक्षा करते हैं।

बिहार और उत्तर प्रदेश का चुनावी महत्त्व

2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एन.डी.ए./एनडीए) ने 31 सीटें जीती थी जब जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा थाद्य जिसमे भाजपा को 22] एलजेपी को 6 और आरएलएसपी को 3 सीटें मिली थी। जेडीयू को 2 और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) के आरजेडी को 4] कांग्रेस को 2 और एनसीपी को 1 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में

जेडीयू के एनडीए में आने के साथ ही 40 में से 39 सीटें एनडीए को प्राप्त हुई जबकि यूपीए को एक सीट मिली जिसमें आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत सकी। 2024 में पुनः इस गठबंधन के उपरांत एनडीए को मात्र 30 (बीजेपी-12] जेडीयू-12] एलजेपी-आर-5] हम-1) सीटें मिली जबकि इंडी अलायन्स (आईएनडीआईए) के आरजेडी को 4] कांग्रेस को 3 सीपीआई-एमएल-को 2 और एक सीट निर्दलीय (राजीव रंजन अलियास पप्पू यादव) को मिली जो अब कांग्रेस में सम्मिलित हो चुके हैं।

जहाँ तक उत्तरप्रदेश की बात है तो 2014 के आम चुनावों में बीजेपी को अकेले 80 में से 71 सीटें (61) मिली, 2019 में 62 (-9) और 2024 में केवल 33 (-29) सीटें मिली हैं।

अखिल भारतीय स्तर पर यदि हम देखें तो इन दो प्रान्तों के चुनाव परिणामों के साथ 2014 में बीजेपी ने 282 (31% वोट) और एनडीए ने 336 सीटें जीतीं। 2019 में बीजेपी को 303 (37-36% वोट) और एनडीए को 353 सीटें मिलीं। किंतु 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को केवल 240 (36-56 % वोट) और एनडीए को 293 सीटें मिलीं।

उपरोक्त गणित से स्वतः सिद्ध हो जाता है कि लोकसभा चुनावों में यूपी और बिहार के कुल 120 सीटें किसी पार्टी को सत्ता तक पहुँचाने या दूर रखने में कितनी अहम भूमिका निभाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि अखिल भारतीय स्तर पर 'अबकी बार 400 पार' का नारा जिसके लिए बिहार की 40 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण थी, जेडीयू से गठबंधन के बावजूद 30 के ऊपर क्यों नहीं गयी ? इसका बिहार में बीजेपी के भविष्य पर क्या प्रभाव हो सकता है ?

### जाति और चुनावी राजनीति

भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले राजनीतिशास्त्री और समाजशास्त्री यह बताते हैं कि भारत में जातियों का राजनीतिकरण हुआ है (कोठारी: 1970), अर्थात् जाति अपने पुराने परंपरागत अर्थ से निकलकर आधुनिक हो गयी है। स्पष्ट है कि मध्य और निम्न जातियाँ जिनकी संख्या ज्यादा है उन्होंने लोकतंत्र में संख्याबल के महत्व को पहचान कर उसके अनुरूप अपना सुदृढीकरण और चुनावों में मत का प्रयोग किया है। यह इस वक्तव्य से अभिव्यक्त होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। आश्चर्य नहीं है कि आज निचली जातियों का विमर्श पहचान और प्रतिष्ठा से अधिक संसाधनों और सत्ता में भागिदारी के लिए ज्यादा मुखर दिखाई देती है। आंद्रे बेते (1970) जैसे समाजशास्त्री यह मानते हैं कि इसने जातियों को और अधिक

महत्वपूर्ण रूप से भारतीय राजनीति में स्थापित किया है जिसका स्पष्ट प्रभाव हमें 1980 के पश्चात निचली जातियों के स्पष्ट उभार के रूप में देख सकते हैं। यही कारण है कि आज अधिकतर क्षेत्रीय दल मात्र अपनी जातीय सामुदायिक पहचान से सम्बंधित की जाती है।

क्षेत्रीय दलों की जातीय समीकरणों को सफलतापूर्वक प्रयोग करने की कला ने राष्ट्रीय दलों को भी ऐसे ही चुनावी समीकरणों के लिए उत्प्रेरित किया है। जिसके अंतर्गत अधिक संख्या वाली जाति के सदस्यों को टिकट देने, जाति विशेष के डमी उम्मीदवार खड़ा कर उस जाति के सीटों को विभाजित करना जैसे हथकंडे राजनीतिक विचारधारा और व्यक्तिगत सामाजिक राजनीतिक पैठ और कुशलता पर भारी पड़ती है। जिसके कारण जाति विभाजित समाजों में कई जातियों में समान पैठ रखने वाले नेताओं का उभार वर्तमान में दुर्लभ घटना बन गयी है।

उपरोक्त विवरणों के आलोक में अब बिहार की चुनावी राजनीति का समझने के प्रयास करते हैं बिहार जातीय सर्वेक्षण 2022 जिसकी रिपोर्ट अक्टूबर 2023 में जारी हुई, प्रदेश में 81-39% हिन्दू, 17-70% मुस्लिम और 0-21% शेष अन्य धार्मिक समुदाय को इंगित करता है इसमें 15-52% सामान्य समुदाय, 63-14% ओबीसी, 19-65% एससी और 1-68% एसटी समुदाय की पहचान करती है। ओबीसी में 27% बीसी और 36% इबीसी है। प्रमुख बीसी जातियों में यादव (14-26%), कोइरी या कुशवाहा (4-2%), कुर्मी (2-8%) और बनिया (2-3%) है।

उपरोक्त जातीय विवरण प्रस्तुत करने का मत यह है कि किसी एक लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण स्थापित करना आसान कार्य नहीं है। उदाहरण के लिए ऐसा माना जाता है कि लालू यादव में अपनी सफलता के दिनों में 'एमवाई' अर्थात् मुस्लिम-यादव (17.7+14.3=32%) को अपना कोर वोट बनाया और आवश्यकतानुसार पार्टी में राजपूत और भूमिहार नेताओं को शामिल कर लगभग 5% और मतों को जोड़ने का प्रयास किया जो कि भारतीय चुनावी पद्धति (फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम) में सफलता हासिल करना संभव बनता है। इसी प्रकार नीतीश कुमार ने लालू यादव के वोट बैंक को शरद यादव के साथ मिलकर और अपनी सेकुलर छवि (या मुस्लिम समर्थक) द्वारा अपनी ओर खींचा इसके साथ ही स्वजातीय 'लव-कुश' (कोइरी-कुर्मी-7%) समीकरण के द्वारा जनसमर्थन प्राप्त किया बीजेपी से सहयोग ने उन्हें उच्च जाति (15%) और बनिया (2-5%) को भी अपने साथ जोड़ा और लगभग दो दशक से बिहार की राजनीति में एकछत्र नेतृत्व प्रदान करने में सक्षम हुए हैं। जिसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण लालू यादव का भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण पतन और उनके शासन काल में बिहार में जंगलराज जैसी स्थिति और आर्थिक स्तर पर लगातार पिछड़ते जाने जैसी घटनाओं ने भरपूर माहौल तैयार किया।

बिहार और लोकसभा चुनाव 2024

यदि वर्तमान लोकसभा के चुनावी परिणामों की बात है तो यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि चुनावों से पहले की दो घटनाओं ने बिहार के जनमानस के राजनीतिक वरीयताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रथम तो यह कि नीतीश कुमार के बार-बार गठबंधन बदलने से उनकी विश्वसनीयता कम हुई और चुनावों के पश्चात् उनकी भूमिका को लेकर भी संदेह बढ़ा। स्मरणीय है कि पिछले विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार बार-बार यह कहते हुए सुने गये कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। अतः जनता भी भविष्य के परिवर्तनों को लेकर संदेहास्पद थी। दूसरा, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मनमाने व्यवहार से परेशान शिक्षकों ने नीतीश के पक्ष में उत्साह नहीं दिखाया जबकि तेजस्वी यादव भी इस बात को चुनाव पूर्व से ही उठाते रहे कि उन्होंने 17 महीनों में 5 लाख शिक्षकों की बहाली कराई न कि नीतीश जी ने।

साथ ही लालू यादव का इन चुनावों के पूर्व सक्रिय होने ने यादव और मुस्लिम वोटों को संगठित किया। किंतु इन सभी के साथ ही भाजपा का 400 पर का वक्तव्य किसी प्रभाव तक एक अहंकार युक्त दावे के रूप में अधिक प्रदर्शित होता रहा जिसने उनके कोर वोटों में भी यह भ्रम फैलता गया कि हम 'मोदी कि गारंटी' के बूते 400 नहीं तो उसके आसपास पहुँच ही जायेंगे और उस मुताबिक प्रयास नहीं हुए।

इसके अतिरिक्त स्थानीय कार्यकर्ताओं के सुझाओं को अनदेखा करके किसी दूसरी-तीसरी पार्टी से भाजपा में आये नेताओं को टिकट देना भी अपेक्षित सफलता नहीं दिला सका। इसका एक अच्छा उदाहरण सातवें चरण के चुनाव में काराकाट सीट से जहाँ उपेन्द्र कुशवाहा (आरएलएसपी) चुनाव लड़ रहे थे वहाँ से निर्दलीय के रूप में भोजपुरी गायक पवन सिंह का चुनाव में शिरकत करना रहा। यहाँ कुशवाहा समुदाय के लोगों ने इसे कुशवाहा समुदाय के वोटों के बांटने और राजपूत प्रतिनिधि के चुने जाने की सम्भावना के रूप में देखा। विदित है कि पहले बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल से अपना प्रत्याशी बनाया था फिर उनका नाम वापस लिया गया जब उनके अश्लील गानों की चर्चा ने बंगाल में स्त्री के सम्मान से जोड़ कर टीएमसी ने प्रचारित करना शुरू किया। इसी क्रम में औरंगाबाद में पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के बावजूद सुनील सिंह को फिर से चुनाव लड़ाने के कारण राजपूतों ने आरा (आर. के. सिंह), और काराकाट (उपेन्द्र कुशवाहा) को भी समर्थन नहीं दिया और सातवें चरण की सातों सीटों से बीजेपी को हाथ धोनी पड़ी।

साथ ही वर्तमान में बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। शकुनी और सम्राट दोनों ही लगभग बिहार की सभी पार्टियों में नेता रह चुके हैं, तात्पर्य यह है कि परिस्थिति के अनुरूप दल बदल रहे हैं। सम्राट चौधरी तो कम उम्र में ही राजद सरकार में मंत्री बन जाने

के कारण राज्यपाल द्वारा बर्खास्त भी हो चुके हैं। सम्राट को उच्च पद पर बैठने का कार्यकर्ताओं का समर्थन नहीं मिला। जबकि बिहार में गठबंधन के दौरान उन्हें उपमुख्यमंत्री का पद देकर भाजपा उन्हीं के नेतृत्व में आगे भी चुनाव लड़ना चाहती हुई प्रतीत होती है चुनाव के पहले सुशील मोदी जी का बीमारी के करना हटन और फिर मृत्यु के साथ ही बिहार में भाजपा के सबसे बड़े नेता और शायद एक मात्र जाने माने नेता का नेतृत्व भी नहीं मिल सका यद्यपि भाजपा ने कभी भी उनके क्षमता पर पूरा भरोसा और समर्थन नहीं किया। यदि यह कहा जाये कि वर्तमान में बिहार में भाजपा के पास एक भी विश्वसनीय चेहरा नहीं है तो गलत नहीं होगा।

भाजपा की वर्तमान चुनावी जीत में उसके कोर वोटर, कुछ हद तक मोदी फैक्टर और जेडीयू से गठजोड़ ही रहा है। यह भी महत्वपूर्ण है कि गिरते जनाधार के बावजूद नीतीश का भाजपा के बराबर सीटें लाना यह दर्शाता है कि भाजपा के वोटर्स ने तो जेडीयू का साथ दिया लेकिन जेडीयू के वोटर्स में शायद असमंजस की स्थिति रही जिससे वोटों का बिखराव हुआ।

बिहार नेतृत्व के संकट की ओर ?

इस विश्लेषण को अगर भविष्य की उभरती प्रवृत्तियों के रूप में देखें तो नेतृत्व का संकट भाजपा और जेडीयू दोनों में ही दिखाई पड़ता है। जेडीयू में नीतीश के बाद कौन एक प्रश्न चिन्ह है। नीतीश ने किसी अन्य नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। जिसका एक तत्कालीन उदाहरण चुनावों के बाद एनडीए गठबंधन की मुख्य पार्टी के रूप में उभरने के बाद भी जेडीयू द्वारा अपने किसी नेता के लिए किसी भी महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं लेना है। ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश पार्टी में दूसरा शक्ति केंद्र नहीं विकसित होने देना चाहते। जिसके उदाहरण पूर्व में भी मौजूद रहे हैं। इसी मध्य नीतीश के पुत्र निशांत कुमार के राजनीति उतराधिकारी के रूप में विचार-विमर्श भी उभर रही है। स्पष्ट है नेतृत्व का संकट भविष्य पर मंडरा रहा है। राजद में भी नेताओं की गिनती लालू परिवार तक ही सिमट गयी है।

जिस बिहार से जे.पी. आन्दोलन ने ऐसे कई नेता दिए जो केंद्र और राज्य में उच्च पदों तक पहुँचे और अभी हल तक वही नेता सक्रिय रहे हैं वही अब जमीनी स्तर का एक भी नेता बिहार में नहीं है। सभी किसी नेता के पुत्र-पुत्री या नातेदार हैं या फिर कुछ अधिकारी नेताओं की चापलूसी के द्वारा पार्टी में सक्रिय हैं। बिहार के लिए यह नेतृत्व का संकट भविष्य के लिए अच्छे संकेत नहीं है। भाजपा के लिए नीतीश के पश्चात् बिहार में अपने को स्थापित करने का सुनहरा मौका नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है। भाजपा और जेडीयू से बहार नेताओं की दूसरी पीढ़ी में भी केवल तेजस्वी और चिराग पासवान ही जनता में अपने पैठ बना पाए हैं जिसके पीछे भी उनके पिता द्वारा तैयार किया गया जनाधार ही काम कर रहा है।



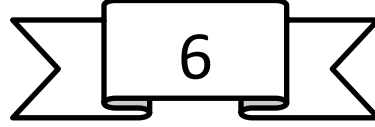
बिहार में स्वतंत्रता के पश्चात् श्री कृष्ण सिन्हा, के. बी. सहाय जैसे कुछ नेता के अतिरिक्त जातिओं में विभाजित समाज का कोई भी सर्वमान्य नेता नहीं उभर सका या यह कहे कि एक बृहत् विचारधारात्मक नेतृत्व प्रदान करने वाला कोई नेता नहीं उभरा। दूसरा यह कि बिहार में राजनीतिक संस्थाओं का संस्थानीकरण नहीं हो सका है (राय और पांडे: 1981)। जिसके दो कारण रहे हैं, एक, राजनीतिक विकास के लिए संस्थाओं में विभेदीकरण का आभाव और उसके अनुरूप भूमिकाओं का आभाव और दूसरा, राजनीतिक सहभागिता बढ़ने के साथ यह आवश्यक है कि संस्थाओं में इसे जगह प्रदान करने की क्षमता हो जिसकी बिहार में कमी रही। जिसके कारण भिन्न-भिन्न गुट बने और व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा ने एक बृहद वैचारिकी का स्थान ले लिया। जिसके कारण राजनीति समावेशी होने के स्थान पर विलगाव की राजनीति आगे बढ़ी। आश्चर्य नहीं है कि राजनीति जातीय पहचान और उससे जुड़े लाभ लेने तक ही सिमट कर रह गयी। वैचारिक संयोजन (आइडियोलॉजिकल कोएलिशन) से अधिक विजयी संजोड़ (विनिंग कॉम्बिनेशन) बनाने का प्रयास किया जाता है। अधिकतर दलों में नेताओं के लिए राजनीतिक अवसर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि अधिकतर दल मात्र एक पारिवारिक कंपनी (फैमिली एंटरप्राइज) के रूप में कम करती है जिसमें बाहरी लोगों की उन्नति एक सिमित स्तर तक ही संभव है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि भाजपा की असफलता और बिहार की राजनीति कही न कही गहरे राजनीतिक नेतृत्व के संकट से गुजर रही है जिसके प्रति चिंतन-मनन राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों को करना होगा।

## संदर्भ सूची:

- Andre Beteille, 'Caste and Political Group Formation in Tamilnad', in Sudipta Kaviraj (ed.), "Politics in India", OUP, New Delhi, 2008 (Eighth Impression), pp.71-93.
- Haridwar Rai and Jawahar Lal Pandey, 'State Politics in India: A Crisis of Political Institutionalism', *IJPS*, Vol-42, No-4, Oct-Dec-1981, pp-45-64.
- Rajni Kothari, 'Caste and Modern Politics', in Sudipta Kaviraj (ed.), "Politics in India", OUP, New Delhi, 2008 (Eighth Impression), pp.57-70.
- Bihar Election Result 2024, Dainik Bhashkar, <https://www.bhaskar.com/election-2024/bihar-loksabha-election/news/bihar-lok-sabha-election-result-2024-analysis-nitish-kumar-bjp-jdu-rjd-candidates-133124183.html> assessed on 15 July 2024
- 2022 Caste Based Survey, [https://en.wikipedia.org/wiki/2022\\_Bihar\\_caste-based\\_survey](https://en.wikipedia.org/wiki/2022_Bihar_caste-based_survey) assessed on 15 July 2024.





## लोकसभा चुनाव 2024: उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में वंशवाद और समाजवादी पार्टी

सुशांत यादव

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मवाना (मेरठ)

समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों की सूची देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में परिवारवादीध्वंशवादी राजनीति को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ले लिया है। पार्टी प्रत्याशियों पर दृष्टि डालें तो लोकसभा की 80 सदस्यीय सीट वाले प्रदेश में सपा प्रमुख ने दस प्रतिशत अर्थात् आठ सीटों पर राजनीतिक वारिसों को टिकट देकर वंशवादी राजनीति को निरंतर विचार-विमर्श का विषय बना हुआ है। यह विचार-विमर्श इस कारण भी अत्यधिक रुचिकर हो जाता है क्योंकि दो सीटों पर ऐसे राजनीतिक वारिसों को टिकट दिया गया है जिन्होंने लोकसभा सदस्य होने की सबसे मूलभूत अहर्ता के रूप में अपनी 25 वर्ष की आयु इसी वर्ष मार्च में या फिर पिछले वर्ष नवंबर में ही पूर्ण की है।

प्रारंभ कैराना से करते हैं जहां कई दक पूर्व हसन परिवार के मुखिया अख्तर हसन ने नगरपालिका परिषद चुनाव में सभासदी का चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके पश्चात् सभासद से अध्यक्ष और फिर वह कैराना लोकसभा सीट से लोकसभा सांसद रहे। अख्तर हसन ने अपने पुत्र मुनव्वर हसन को सियासी मैदान में उतारा जो सबसे कम उम्र में चारों सदनों के सदस्य रहे। मुस्लिम समाज में मुनव्वर हसन पश्चिमी यूपी के बड़े नेता के तौर पर छाप छोड़ी। उनके दिवंगत होने के पश्चात् उनकी पत्नी तबस्सुम बेगम कैराना लोकसभा सीट से दो बार लोकसभा सांसद रही। उनके बेटे नाहिद हसन ने भी चुनावी राजनीति में पदार्पण किया और 2014 में कैराना विधानसभा से उपचुनाव जीत कर पहली बार विधायक बने। कैराना से निरंतर तीसरी बार विधायक नाहिद हसन की छोटी बहन 28 वर्षीय इकरा हसन को समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर उतारकर हसन परिवार की तीसरी पीढ़ी की दूसरी बेल को पुष्पित होने के लिए चुनावी मैदान जैसी उर्वर भूमि प्रदान कर दी है। कैराना से आगे बढ़ें तो बिजनौर लोकसभा सीट पर सपा

प्रत्याशी को लेकर कई दिनों तक कई नामों का विचार-विमर्श होता रहा। विचार-विमर्शों पर विराम लगाते हुए यशवीर सिंह धोबी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया लेकिन अंतिम समय में टिकट में बदलाव करते हुए नूरपुर विधानसभा से वर्तमान सपा विधायक रामअवतार सैनी के पुत्र 35 वर्षीय दीपक सैनी को यहाँ का प्रत्याशी बनाया गया है। इसी प्रकार समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद रहे डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के उत्तराधिकारी के रूप में उनके पौत्र मुरादाबाद के कुंदरकी के विधायक जियाउर्रहमान बर्क को टिकट देकर संभल की सीट सपा ने बर्क परिवार के जिम्मे कर दी है। युवा जियाउर्रहमान बर्क ने महज 26 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखा। राजनीति का ककहरा अपने दादा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क से सीखने वाले जियाउर्रहमान बर्क ने पहला चुनाव 2017 में एआइएमआइएम से लड़ा और हार गए। इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में कुंदरकी विधानसभा से यहाँ के सीटिंग विधायक का टिकट काटकर सपा ने जियाउर्रहमान बर्क को चुनाव लड़ने का अवसर दिया। सीटिंग विधायक का टिकट कटने के कारण यहाँ तमाम विरोध के पश्चात भी जियाउर्रहमान बर्क ने यह सीट 44 हजार वोट के अंतर से जीत लिया। इसके बाद अचानक से बीमार हुए डा शफीकुर्रहमान बर्क के निधन के पश्चात उन्हें संभल की लोकसभा सीट पर उनका उत्तराधिकारी मानते हुए उन्हें सपा ने अपना प्रत्याशी बना दिया है।

हमीरपुर लोकसभा सीट से सपा ने चरखारी के पूर्व विधायक के पुत्र अर्जेन्द्र सिंह राजपूत को प्रत्याशी घोषित किया है। अर्जेन्द्र सिंह राजपूत मूलरूप से महोबा जनपद के ग्राम कनकुआ के रहने वाले हैं और लोधी जाति से आते हैं। इनके पिता चंद्रनारायण सिंह राजपूत 1967 में जनसंघ से चरखारी विधान सभा से विधायक रह चुके हैं। 1974 में महोबा सदर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से विधायक बन चुके हैं। कौशांबी में वंशवादी राजनीति का मामला तो सबसे दिलचस्प है। सपा ने इस बार यहाँ से देश के प्रायः सबसे युवा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया है जो इसी साल 1 मार्च को 25 साल की आयु पूर्ण करेंगे जोकि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम अहर्ता है। वह सपा के महासचिव और 5 बार के विधायक रहे इंद्रजीत सरोज के सुपुत्र हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इंद्रजीत सरोज को सपा ने कौशांबी से अपना उम्मीदवार बनाया लेकिन उन्हें चुनाव में भाजपा के विनोद सोनकर ने हरा दिया। इसके पश्चात सपा के टिकट पर इंद्रजीत सरोज ने मंझनपुर सीट से साल 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उन्हें जीत हासिल हुई। अब सपा ने उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट देकर सराज परिवार की राजनीतिक वृक्ष को और घना होने का अवसर दे दिया है। कुछ इसी तरह की वंशवादी राजनीति की कहानी गोंडा में भी देखने को मिल रही है। यहाँ सपा ने श्रेया वर्मा को टिकट दिया है जो समाजवादी पार्टी के

कदावर नेता स्व. बेनी प्रसाद वर्मा की पोती हैं और सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे राकेश वर्मा की बेटी हैं। श्रेया वर्मा बेनी प्रसाद वर्मा की राजनीतिक विरासत की तीसरी पीढ़ी हैं। गोंडा से आगे पूर्वांचल के की ओर बढ़ें तो कुशीनगर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी के रूप में अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सैथवार चुनावी मैदान में हैं। उनके पिता दिवंगत जन्मेजय सिंह भाजपा से देवरिया विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक रहे हैं। वर्ष 2020 में उनकी मृत्यु की पश्चात होने वाले उपचुनाव में उनके बेटे पिंटू सैथवार भाजपा से टिकट पाने की प्रयास करते रहे मगर टिकट पाने में असफल रहे और अंततः निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और लगभग बीस हजार मतों के साथ चौथे स्थान पर रहे। जन्मेजय सिंह की चुनावी राजनीति को वंश परंपरा में परिवर्तन करते हुए सपा ने उनके बेटे पिंटू सैथवार को 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में देवरिया विधानसभा सीट से टिकट देकर चुनाव लड़वाया जिसमें उन्हें पुनः पराजय का सामना करना पड़ा। अब उन्हीं पिंटू सैथवार को सपा से फिर से कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। वह अपनी पिता की राजनीतिक विरासत को पाने में सफल हो पाते हैं या कि नहीं यह तो 4 जून को घोषित होने वाला चुनाव परिणाम ही बता पाएगा किंतु सपा ने उनको टिकट देकर वंशवादी राजनीति में वृद्धि को थोड़ा और सरल अवश्य कर दिया है।

समाजवादी पार्टी की ओर से इस प्रकार की वंशवादी राजनीति को बढ़ावा देने का अंतिम उदाहरण मछलीशहर लोकसभा सीट से घोषित पार्टी की प्रत्याशी प्रिया सरोज हैं। प्रिया पूर्व सांसद और जौनपुर के केराकत से मौजूदा विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। प्रिया के पिता तूफानो सरोज 1999 से 2004 और 2004 से 2009 तक परिसीमन के पूर्व की गाजीपुर जिले की सैदपुर सीट से सांसद रहे हैं। 2009 में मछलीशहर सीट से सांसद चुने गए। 2014 में भी मछलीशहर से लड़े किंतु चुनाव हार गए और तीसरे स्थान पर रहे। 2022 में राज्य विधानसभा चुनाव में मछलीशहर की केराकत सीट से विधायक बन गए। उनकी बेटी प्रिया सरोज चार बहनों व एक भाई के बीच तीसरे नंबर पर आती हैं। जब वह जन्मीं तो सरोज परिवार के जैसे भाग्य ही खुल गए। वर्ष 1998 में उनका जन्म हुआ और पिता तूफानी सरोज वर्ष 1999 में सांसद बन गए। जो निरंतर तीन बार सांसद रहे। पिता दिल्ली पहुंचे तो प्रिया की परवरिश और पढ़ाई लुटियन के माहौल में हुई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और पेशे के रूप में वकालत की शुरुआत सीधे सर्वोच्च न्यायालय से की। और अब चुनावी राजनीति में सीधे लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। प्रिया सरोज ने पिछले साल नवंबर में ही 25 वर्ष की आयु पूर्ण की। सपा से टिकट प्राप्त

करने के साथ ही उन्होंने सियासत में कदम रखते हुए पिता की राजनीतिक विरासत को सम्हालने के लिए चुनावी बल शुरू कर दी है।

समाजवादी पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है जिसके अंतर्गत 80 में से 53 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इन आठ प्रत्याशियों के अतिरिक्त यदि अखिलेश के परिवार से लड़ने वालों को जोड़ लें तो 57 में से 13 प्रत्याशी अर्थात् समाजवादी पार्टी के कुल प्रत्याशियों के लगभग 20 प्रतिशत से अधिक प्रत्याशी तो अपनी राजनीतिक विरासत बचाने या संभालने के लिए चुनावी मैदान में हैं। अखिलेश के अपने परिवार के अतिरिक्त उपर्युक्त आठों प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन्हें सपा ने इस लोकसभा चुनाव में या तो पहली बार टिकट दिया है या फिर दो वर्ष पूर्व हुए राज्य विधानसभा चुनाव में ही उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत कराई है। इतनी बड़ी संख्या में राजनीतिक परिवार के लोगों को टिकट देना लोकतंत्र के वास्तविक निहितार्थ को धूमिल करना है। जब एक ही परिवार के लोग बार-बार चुनाव जीत कर या फिर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारे जाएँगे तो लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन की अवधारणा कहाँ धरातल पर उतर पाएगी।

चुनाव विश्लेषक रहे योगेन्द्र यादव ने 2019 के लोकसभा चुनाव के पश्चात लोकतांत्रिक विरोधाभास शीर्षक के तहत एक लेख लिखा और बताया कि भारतीय लोकतंत्र की चुनावी राजनीति में 1952 से लेकर 2019 तक हुए चुनावों में महज कुछ हजार लोग ही हैं जो बार-बार चुनाव जीतकर आते हैं और राजनीतिक सत्ता का निरंतर दोहन करते हैं। सहभागी लोकतंत्र में पार्टियों का भी यह दायित्व बनता है कि वह अधिक से अधिक लोगों को न केवल चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित करे अपितु अच्छे, पढ़े-लिखे, जागरूक लोगों को प्रत्यक्ष राजनीति में सहभागी होने के लिए भी प्रेरित करे। किंतु प्रदेश का दुर्भाग्य देखिए कि यहाँ का सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी ही राज्य के नागरिकों को चुनावी राजनीति में आने के लिए प्रेरित करने की जगह वंशवादी राजनीति को ही बढ़ावा देने में अपनी ऊर्जा समाप्त कर दे रही है जो लोकतंत्र के अर्थों के बिल्कुल विपरीत है।

संदर्भ सूची:

- <https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha/lok-sabha-elections-2024-full-list-of-samajwadi-party-candidates-and-their-constituencies/article68086943.ece>
- <https://results.eci.gov.in/PcResultGenJune2024/partywisewinresultState-1680.htm>
- <https://timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/uttar-pradesh-lok-sabha-election-results-2024-full-and-final-list-of-winners-including-narendra-modi-rahul-gandhi-akhilesh-yadav-and-more/articleshow/110729194.cms>







Aiming High, Touching Sky

सी जी एस  
वैश्विक अध्ययन केंद्र  
(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)  
अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन  
गुरु तेग बहादुर मार्ग  
दिल्ली विश्वविद्यालय  
दिल्ली- 110007